

मुकदमों का विवरण

सौम्या चौरसिया बनाम.

प्रवर्तन का निर्देश (2023 की आपराधिक अपील No.3840) 14 दिसंबर, 2023

[अनिरुद्ध बोस और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित अपीलार्थी ने यू/एस के नेतृत्व में जमानत याचिका खारिज कर दी। 439 Cr.P.C ने इस अपील को प्राथमिकता दी है। (i) क्या अपीलार्थी प्रथम दृष्टया धनशोधन के अपराध में शामिल पाया गया था। 3 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; (ii) क्या अपीलार्थी को एक महिला होने के नाते प्रथम परंतुक का लाभ एस को दिया जाना चाहिए। 45 पी. एम. एल. ए. का; (iii) क्या सारांश, तिथियों की सूची, कानून के प्रश्नों और एस. एल. पी. में इन आधारों पर आरोप लगाते हुए एक निर्लज्ज प्रयास करने की कोशिश की गई थी कि उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र और संज्ञान आदेश की सराहना नहीं करने में घोर गलती की थी।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - एस. 3 और एस. 45 - एक 'एस' के खिलाफ यू/एस के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 186, 204, 120-आई. पी. सी. का बी, 353 और 384-इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने एक ई. सी. आई. आर. दर्ज किया और अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया-विशेष अदालत ने अपीलार्थी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया-फिर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका का नेतृत्व किया-जब उच्च न्यायालय में जमानत याचिका में फैसले की प्रतीक्षा की जा रही थी, तो पुलिस ने आरोपी 'एस' के खिलाफ आरोप पत्र का नेतृत्व किया-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यू/एस. का संज्ञान लिया। 204 और 'एस' के खिलाफ प्रस्तुत आरोप-पत्र पर आई. पी. सी. की 353-जिसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: अपीलार्थी और अन्य व्यक्तियों 'एम' और 'ए' के बीच अपीलार्थी और 'एस' के बीच मजबूत संबंधों से संबंधित साक्ष्य; साक्ष्य 849

848

सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशक 850

'एस' द्वारा संचालित जबरन वसूली सिंडिकेट से अर्जित धन को अपीलार्थी के प्रतिनिधि 'एम' में स्थानांतरित करना; अपराध की आय का उपयोग और अपीलार्थी द्वारा अपनी माँ और चचेरे भाई 'ए' के नाम पर संपत्तियों के अधिग्रहण के साथ-साथ उक्त संपत्तियों आदि के विवरण का विवरण उक्त अभियोजन शिकायत में दिया गया है, जो न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि प्रथम दृष्टया अपीलार्थी को धन शोधन के अपराध में शामिल पाया गया है। 3 उक्त अधिनियम के-

न्यायालयों को प्रथम परंतुक का लाभ एस को देते समय अपने विवेक का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए।<sup>45</sup> पी. एम. एल. ए. उन व्यक्तियों की श्रेणी के लिए (एक व्यक्ति जो सोलह वर्ष से कम आयु का है या एक महिला है या बीमार है या असंवैधानिक है) जिसमें उल्लेख किया गया है-कथित अपराधों में ऐसी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की संलिप्तता की सीमा, जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की प्रकृति आदि, भौतिक विचार होंगे-तत्काल मामले में, प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र किए गए पर्याप्त साक्ष्य हैं जो प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलकर्ता जो मुख्यमंत्री के कार्यालय में उप सचिव और ओ. एस. डी. था, धन शोधन के अपराध में सक्रिय रूप से शामिल था, जैसा कि एस.3 पी. एम. एल. ए.-इसके विपरीत, न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी कथित अपराध और विशेष लाभ के लिए दोषी नहीं है जैसा कि एस.45 अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए जो एक महिला है।[पैरा 21,24,25]

धन शोधन निवारण अधिनियम, **2002**-दंड प्रक्रिया संहिता, **1973**-आई. ओ. द्वारा आरोप पत्र में उल्लिखित आरोप शून्य नहीं हैं-यह न्यायालय है जो यह तय करता है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है या नहीं।

आयोजित किया गया:जब एफ. आई. आर. विशेष ऑफ एनसेस के तहत दर्ज की जाती है, जिसमें पी. एम. एल. ए. की अनुसूची में उल्लिखित ऑफ एनसेस शामिल होते हैं, तो यह सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत होती है, जो यह तय करेगी कि आरोपी के खिलाफ निर्धारित ऑफ एनस के लिए आरोप तैयार करने की आवश्यकता है या नहीं-आई. ओ. द्वारा आरोप पत्र में उल्लिखित ऑफ एनस को कभी भी अंतिम निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है कि क्या पी. एम. एल. ए. में निर्धारित ऑफ एनस मौजूद थे या नहीं, विशेष रूप से जब अभियुक्त के खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर. में इनका उल्लेख किया गया था।[पैरा 28]

उच्चतम न्यायालय नियम, **2013** -आर. **3 Or.XXI**-अपीलार्थी द्वारा और उसकी ओर से तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

अपील में गलत बयान-उच्चतम न्यायालय के नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार एसएलपी के अंत में अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र और याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के नेतृत्व में या उसकी ओर से जारी किया जाने वाला हलफनामा कानून की नजर में पवित्रता रखता है:

आयोजित किया गया:तत्काल अपील में, हालांकि दस्तावेज, विशेष रूप से दिनांकित आई. डी. 2 की आरोप-पत्र और दिनांकित आई. डी. 1 का संज्ञान आदेश न तो दलीलों का हिस्सा थे और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों के दौरान पेश किए गए थे, एस. एल. पी. के अंत में प्रमाण पत्र

अपीलार्थी की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा दिए गए तथ्यों की पुष्टि किए बिना दिया गया प्रतीत होता है जो अन्यथा रिकॉर्ड से बहुत स्पष्ट थे-यहां तक कि न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रश्न के अनुसार एफ़. आई. डेविड को भी (जब उक्त आरोप-पत्र दिनांकित आई. डी. 2 को उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था) प्रश्न का उत्तर देने के लिए निर्देशित नहीं किया गया था, बल्कि एफ़. आई.[पैरा 9,10,11 और 30]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 929-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 3840।

2023 के एम. सी. आर. सी. सं. 1258 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दिनांक 23.06.2023 के निर्णय और आदेश से।

851

सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशक

रूप:

सिद्धार्थ अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अर्शदीप सिंह खुराना, मलक मनीष भट्ट, हर्षवर्धन परगणिया, सुश्री नीहा नागपाल, आदित्य चोपड़ा, मंदीप सिंह, सुश्री अर्शिया घोष, सिदक आनंद, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।एस. वी. राजू, ए. एस. जी., मुकेश कुमार मारोरिया, जोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, सुश्री साइरिका राजू, चंद्र प्रकाश, अर्काज कुमार, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा बिलासपुर में विविध आपराधिक मामला सं. 1258/2023 में पारित दिनांकित 23.06.2023 आदेश पर वर्तमान अपील के माध्यम से हमला किया गया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने Cr.P.C की धारा 439 के तहत अपीलार्थी के नेतृत्व में जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। अपीलार्थी को अपराध सं. ई. सी. आई. आर./आर. पी. जेड. 0/09/2022 दिनांक 29.09.2022, पुलिस स्टेशन/जांच एजेंसी-प्रवर्तन निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ में आई. पी. सी. की धारा 186,204,353,384,120-बी और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 (संक्षेप में "पी. एम. एल. अधिनियम") के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है।

3. अनावश्यक विवरणों से कटा हुआ, रिकॉर्ड से संक्षेप में सामने आने वाले तथ्यों को नीचे दिया जा सकता है:

| तिथियाँ    | विशिष्टताएँ                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.06.2022 | आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत सूर्यकांत तिवारी नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई, जो तलाशी और जब्ती के समय कमरा संख्या 664, होटल शेरेटन ग्रैंड, व्हाइटफी एल्ड, बेंगलुरु में पाया गया था। |

852

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

|            |                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.07.2022 | आयकर जांच के उप निदेशक श्री पक्किरेश बदामी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 186, 204, 120-बी और 353 के तहत कथित सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ बेंगलुरु शहर |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>के काडुगोडी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की। बाद में आई. पी. सी. की धारा 384 को 03.09.2022 पर जोड़ा गया।</p>                                                                                                                       |
| 29.09.2022 | <p>प्रवर्तन निदेशालय (इसके बाद "ईडी" के रूप में संदर्भित) ने एक ईसीआईआर दर्ज किया जिसमें सं. आर. पी. जेड. ओ./09/2022 उक्त अभियुक्त-सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ दर्ज उक्त एफ. आई. आर. के आधार पर।</p>                                       |
| 02.12.2022 | <p>अपीलार्थी-सौम्या चौरसिया, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कार्यालय में उप सचिव थीं, को उक्त ईसीआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्हें 06.12.2022 तक ईडी हिरासत में भेज दिया गया था, जिसे विशेष अदालत ने 10.12.2022 तक बढ़ा दिया था।</p> |
| 09.12.2022 | <p>ईडी ने आरोपी सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 3 के तहत अभियोजन</p>                                                                                                                                      |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | शिकायत दर्ज की।                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.12.2022 | ईडी ने अपीलार्थी की चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की, हालांकि, विशेष अदालत ने शुरू में पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत प्रदान की, जिसे बाद में ईडी के कहने पर समय-समय पर आईडी 1 तक बढ़ाया गया।                                           |
| 13.01.2023 | अपीलार्थी ने रायपुर, छत्तीसगढ़ (इसके बाद 'विशेष न्यायालय' के रूप में संदर्भित) में चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए) की अदालत में पीएमएलए की धारा 45 और 65 के साथ पठित Cr.P.C की धारा 437 के तहत एक आवेदन का नेतृत्व किया। |
| 20.01.2023 | विशेष अदालत ने अपीलार्थी की जमानत याचिका खारिज कर दी।                                                                                                                                                                                            |
| 30.01.2023 | ईडी ने अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नामित करते हुए एक पूरक शिकायत का नेतृत्व किया।                                                                                                                                                           |

853

सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशक [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

|            |              |
|------------|--------------|
| 10.02.2023 | अपीलार्थी ने |
|------------|--------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>बिलासपुर में<br/>छत्तीसगढ़<br/>उच्च न्यायालय<br/>के समक्ष<br/>2023 का<br/>1258 नंबर<br/>का जमानत<br/>आवेदन दायर<br/>किया।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.04.2023 | <p>पक्षकारसभक लेल<br/>विद्वान वकीलक<br/>द्वारा दलीलबाजी<br/>कयल गेल आ<br/>जमानत आवेदन<br/>उच्च न्यायालयक<br/>आदेशक लेल<br/>सुरक्षित राखल<br/>गेल।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08.06.2023 | <p>जब उच्च न्यायालय<br/>में जमानत<br/>याचिका में फैसले<br/>की प्रतीक्षा की जा<br/>रही थी, तो<br/>कर्नाटक पुलिस ने<br/>आरोपी-सूर्यकांत<br/>तिवारी के खिलाफ<br/>आई. पी. सी. की<br/>धारा 204 और<br/>353 के तहत<br/>अपराध के लिए<br/>प्राथमिकी संख्या<br/>129/2022 के<br/>संबंध में आरोप<br/>पत्र का नेतृत्व<br/>किया, जिसमें स्पष्ट<br/>किया गया कि<br/>"आरोपी ने<br/>छत्तीसगढ़ राज्य में<br/>अपने गुर्गों के साथ<br/>आई. पी. सी. की<br/>धारा 384 के तहत<br/>अपराध किया है,<br/>जिसके लिए उचित<br/>माध्यम से<br/>छत्तीसगढ़ पुलिस<br/>से रिपोर्ट मांगी<br/>जाएगी।"</p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.06.2023 | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेंगलुरु ने कर्नाटक पुलिस द्वारा सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ प्रस्तुत आरोप पत्र पर आईपीसी की धारा 204 और 353 के तहत संज्ञान लिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23.06.2023 | बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27.06.2023 | <p>शिकायतकर्ता-एफ. आई. आर. नं. 129/2022 एफ. आई. के श्री बादामी ने कडुगोडी पुलिस स्टेशन के माध्यम से कर्नाटक राज्य पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई एफ. आई. एन. एल. रिपोर्ट के खिलाफ एफ. आई. डी. 1 की धारा 173 (8) के तहत एक विरोध याचिका का नेतृत्व किया और आई. पी. सी. की धारा 120-बी और 384 के तहत एफ. आई. एस. की जाँच पूरी करने के लिए प्रार्थना की और मामले की आगे की जाँच करने की अनुमति मांगी और पी. एम. एल. ए. के निर्धारित एफ. आई. एस. के तहत पूरक आरोप</p> |

4. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के विवादित आदेश से व्यथित होने के कारण अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस अपील को प्राथमिकता दी है।

854

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

5. दिलचस्प बात यह है कि तारीखों और घटनाओं की सूची के सारांश में और एस. एल. पी. के ज्ञापन में विभिन्न स्थानों पर अपीलकर्ता ने शिकायत की है कि उच्च न्यायालय विवादित आदेश में यह समझने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अनुसूचित आदेश नहीं बनाया गया था, क्योंकि आई. पी. सी. की धारा 384 और 120-बी के तहत निर्धारित आदेश पहले ही अभियुक्त-सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ जांच अधिकारी के नेतृत्व में आई. पी. सी. की धारा 204 और 353 के तहत आरोप पत्र से हटा दिए गए थे, और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेंगलुरु ने भी केवल आई. पी. सी. की धारा 204 और 353 के तहत आदेश का संज्ञान लिया था। अपीलार्थी ने कानून 'सी' और 'ई' के प्रश्न भी तैयार किए थे और विवादित आदेश को लागू करने के लिए एसएलपी में उस संबंध में 'सी' और 'डी' का आधार उठाया था, इस बात पर जोर देते हुए कि उच्च न्यायालय ने उक्त आरोप पत्र दिनांक 08.06.2023 और दिनांक 16.06.2023 के संज्ञान आदेश पर विचार नहीं करने में भारी त्रुटि की थी।

6. जैसा कि अभिलेख से यह स्पष्ट था कि निर्णय 17.04.2023 पर सुरक्षित रखा गया था और उच्च न्यायालय द्वारा 23.06.2023 पर दिया गया था और विधेय में आरोप पत्र 08.06.2023 पर प्रस्तुत किया गया था और उस पर संज्ञान आदेश 16.06.2023 पर पारित किया गया था, जो उस अवधि के दौरान है जब दलीलें समाप्त होने के बाद निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही थी, इस न्यायालय ने 09.10.2023 पर, जब SLP (तत्काल अपील) की सुनवाई की जा रही थी, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील से एक प्रश्न पूछा कि क्या उक्त आरोप पत्र दिनांक 08.06.2023 और संज्ञान आदेश दिनांक 16.06.2023 को प्रस्तुत किया गया था और उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था। उस समय न्यायालय ने एस. एल. पी. के अंत में अपीलार्थी की ओर से पेश अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र और अपीलार्थी की ओर से एफ. आई. डेविट फ़ाई के बारे में भी विद्वान वकील के ध्यान में लाया। चूंकि, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि उक्त आरोप-पत्र और संज्ञान आदेश प्रस्तुत किए गए थे और उन्हें उच्च न्यायालय के संज्ञान में भी लाया गया था, इसलिए इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि अपीलकर्ता या उनकी ओर से संबंधित अधिवक्ता 09.10.2023 पर आदेश पारित करके उस संबंध में एक हलफनामा दायर कर सकते हैं।

7. अपीलार्थी ने दिनांक **09.10.2023 FI** के उक्त आदेश के अनुपालन में एक शपथ पत्र का नेतृत्व किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहा गया है:-

“4. चूंकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इन तथ्यों का याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर असर पड़ा था, इसलिए इन्हें दिनांकित 19.06.2023 के एक आवरण ज्ञापन के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखे जाने की मांग की गई थी।

855

सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशक [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 856

5. उक्त आवरण ज्ञापन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं:-

A. मायरा मोदी की मेडिकल रिपोर्ट।

ख. मामले में हुए बाद के विकास के आदेश पत्र।

एम. सी. आर. सी. सं. 1258/2023 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवरण ज्ञापन की एक प्रमाणित संपादित प्रति इसके साथ संलग्न की गई है और इसे अनुलग्नक ए के रूप में चिह्नित किया गया है।

6. उक्त आवरण ज्ञापन और संलग्न दस्तावेजों को एल. डी. पर प्रस्तुत करने के बाद। ईडी की ओर से पेश वकील ने 19.06.2023 पर माननीय उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के साथ इसका नेतृत्व किया और उसके बाद एल. डी. के समक्ष इसका उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और इन तथ्यों को मौखिक रूप से एल. डी. के संज्ञान में लाया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश।...

7. जबकि मामले का उल्लेख किया गया था और माननीय उच्च न्यायालय को मौखिक रूप से उन दस्तावेजों की सामग्री के बारे में सूचित किया गया था जो दिनांकित 16.06.2023 के संज्ञान आदेश सहित थे, न तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत तर्क मांगे गए थे, न ही उन्हें आगे बढ़ाया गया था।.....”

8. चूंकि, अपीलार्थी उपरोक्त हलफनामे में आसानी से चुप रहा था कि क्या दिनांकित आरोप पत्र वास्तव में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था या नहीं, इसलिए न्यायालय ने फिर से सवाल उठाया कि उक्त दिनांकित आरोप पत्र उच्च न्यायालय के समक्ष कब पेश किया गया था। इसके जवाब में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि 08.06.2023 दिनांकित आरोप पत्र अपने आप में प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि वह अपीलार्थी के पास उपलब्ध नहीं था। इसलिए, अदालत ने विद्वान वरिष्ठ वकील से एसएलपी के अंत में अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र से जुड़ी पवित्रता के बारे में पूछा, जिसमें कहा गया था कि "एसएलपी केवल अदालत/न्यायाधिकरण के समक्ष दलीलों के लिए है, जिसके आदेश को चुनौती दी गई है और उन कार्यवाहियों में अन्य दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है। इसमें कोई अतिरिक्त तथ्य/दस्तावेज या आधार नहीं लिया गया है या एसएलपी में इस पर भरोसा नहीं किया गया है। "विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जवाब दिया कि "हमें इसके लिए खेद है।"

9. उपरोक्त तथ्यों को विस्तार से बताने का कारण यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 का आदेश XXI, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाओं के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है। उक्त आदेश XXI के नियम 3 में अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश दिया गया है कि एसएलपी को केवल उस अदालत/न्यायाधिकरण के समक्ष दलीलों के लिए स्वीकार किया जाएगा, जिसके आदेश को चुनौती दी गई है और याचिकाकर्ता ऐसी याचिका/दस्तावेजों की प्रतियां पेश कर सकता है जो मामले में रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, यदि और याचिका में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक सीमा तक, या याचिका के अनुलग्नक के रूप में एसएलपी में आग्रह किए गए आधारों को बनाने के लिए। 10. तत्काल अपील में, जैसा कि ऊपर प्रदर्शित किया गया है, हालांकि दस्तावेज, विशेष रूप से दिनांक 1 की आरोप पत्र और दिनांक 2 का संज्ञान आदेश न तो दलीलों का हिस्सा थे और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों के दौरान पेश किए गए थे, एसएलपी के अंत में प्रमाण पत्र अपीलार्थी की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा उन तथ्यों को सत्यापित किए बिना दिया गया प्रतीत होता है जो अन्यथा रिकॉर्ड से बहुत स्पष्ट थे। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता श्री सौरभ के पति और पैरोकर ने भी उक्त तथ्यों की पुष्टि किए बिना एस. एल. पी. के आधार पर आरोप लगाया था। यहां तक कि अदालत द्वारा उठाए गए प्रश्न के अनुसार दायर किए जाने की मांग करने वाले एफिडेविट को भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं किया गया था, बल्कि अस्पष्ट बयान देने के लिए प्रेरित किया गया था।

11. यद्यपि उक्त आरोप पत्र और संज्ञान आदेश को न तो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और न ही बहस की गई थी, लेकिन सारांश, तिथियों की सूची, कानून के प्रश्नों और एसएलपी में इन आधारों पर आरोप लगाते हुए एक लापरवाह प्रयास करने का प्रयास किया गया था कि उच्च न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों की सराहना नहीं करने में घोर गलती की थी।

12. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय के पास यह मानने का कारण है कि अपीलार्थी द्वारा और उसकी ओर से विवादित आदेश को चुनौती देने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का एक साहसिक प्रयास किया गया था।

13. उच्चतम न्यायालय के नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार एसएलपी के अंत में अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र और याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के नेतृत्व में या उनकी ओर से जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र कानून की नजर में पवित्रता रखता है। यह अविश्वसनीय है कि अपीलार्थी की ओर से पेश वकीलों के समूह ने इस स्पष्ट तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जब उच्च 857 से पहले आरोप पत्र और संज्ञान आदेश मौजूद नहीं थे

जब अदालत में दलीलें समाप्त हो गईं और फैसला सुरक्षित रखा गया, तो उच्च न्यायालय द्वारा उस पर विचार न करने को इस अदालत के समक्ष एसएलपी में उक्त आदेश को चुनौती देने का आधार नहीं बनाया जा सका।

14. यह नहीं कहा जा सकता है कि न्याय की मांग करने वाले प्रत्येक पक्ष से भौतिक तथ्यों का पूर्ण और सही खुलासा करने की अपेक्षा की जाती है और यह कि प्रत्येक अधिवक्ता अदालत का अधिकारी होने के नाते, हालांकि किसी विशेष पक्ष की ओर से पेश होता है, उससे न्याय देने के लिए अपने कार्य को पूरा करने में अदालत की निष्पक्ष रूप से सहायता करने की अपेक्षा की जाती है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं, विशेष रूप से नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं से पेशेवरता और कानूनी कौशल के बहुत उच्च मानक की अपेक्षा की जाती है ताकि उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा उनकी व्यावसायिकता का पालन किया जा सके और उनका अनुकरण किया जा सके। हालांकि यह सच है कि अधिवक्ता अपने मुवक्किलों द्वारा दिए गए निर्देशों पर दलीलों का निपटारा करेंगे और अदालतों में बहस करेंगे, लेकिन अपने कानूनी कौशल का उपयोग करके मामले के रिकॉर्ड से तथ्यों को लगन से सत्यापित करने के उनके कर्तव्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

15. तत्काल मामले में, हालांकि न्यायालय ने एस. एल. पी. में उल्लिखित आधारों में और एस. एल. पी. के नीचे दिए गए प्रमाण पत्र और एफ़ी डेविट फ़ाई में दिखाई देने वाली पूर्व-प्रत्यक्ष विसंगतियों के संबंध में अपीलार्थी की ओर से पेश होने वाले सभी विद्वान वकीलों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया था, दिनांकित 09.10.2023 के आदेश के अनुसार, फिर से फ़िंग द्वारा एक चतुराई से तैयार किए गए एफ़ी डेविट द्वारा अदालत द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने से बचने का प्रयास किया गया था। अपीलार्थी द्वारा और उसकी ओर से किए गए इस तरह के प्रयास की कड़ी निंदा की जाती है। इस प्रकार, अपील को केवल उसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि, चूंकि पक्षों के विद्वान वकीलों ने विस्तार से अपनी दलीलें दी हैं, इसलिए न्यायालय अपील को स्वतंत्र रूप से और गुण-दोष के आधार पर भी निपटना उचित समझता है।

**16. अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:-**

(i) अपीलार्थी का नाम न तो आई. डी. 3 दिनांकित एफ. आई. आर. में था और न ही अभियुक्त-सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ दर्ज आई. डी. 2 दिनांकित आई. सी. आई. आर. में, फिर भी अपीलार्थी को आई. डी. 1 पर गिरफ्तार किया गया था, हालांकि उसने ई. डी. द्वारा पूछताछ के दौरान सहयोग किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

((ii) अभियुक्त-सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ आई. पी. आर. संख्या 129/2022 में आरोप-पत्र का नेतृत्व कर्नाटक पुलिस ने केवल धारा 204 और 353 के तहत किया था, आई. पी. सी. की धारा

384 और 120-बी के संबंध में कार्यवाही को उक्त आरोप-पत्र के संबंध में जीवित नहीं कहा जा सकता है।((ग) पी. एम. एल. ए. के अधीन कार्यवाहियां अनुसूचित कार्यवाहियों के अस्तित्व पर निर्भर करती हैं, और इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, पी. एम. एल. ए. के अधीन किसी भी कार्यवाहियों को व्यक्ति की अनुपस्थिति में या अनुसूचित कार्यवाहियों के अलगाव में जारी नहीं रखा जा सकता है।

विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। **1.**

**(एसएलपी (सीआरएल) 2014 का सं. 4634)।**

(iv) धारा 45 के प्रावधान को लागू करते हुए, यह निवेदन किया गया कि अपीलकर्ता एक महिला होने के नाते, उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब वह एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में है और जब निरंतर हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

(v) उसके खिलाफ दर्ज अभियोजन शिकायत में लगाए गए नंगे आरोपों के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं था, और इसलिए धारा 45 में निहित अनुमान का खंडन करने वाले प्रश्न उत्पन्न नहीं हुए।

(vi) ईडी के नेतृत्व में अभियोजन शिकायत में अपीलार्थी और सह-अभियुक्त-सूर्यकांत तिवारी, मनीष उपाध्याय या निखिल चंद्राकर के बीच कोई प्रथम दृष्टया संबंध या संबंध नहीं था, और न ही ईडी द्वारा कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य कोई सबूत पेश किया गया है।

**17. प्रतिवादी-ईडी की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री एस. वी. राजू ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:**

(i) जाँच के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों के बीच मजबूत सांठगांठ दिखाने वाले ठोस साक्ष्य एकत्र किए हैं, और अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ अपीलार्थी के हाथों धन शोधन स्थापित करने वाली प्रथम दृष्टया सामग्री का संकेत देते हैं।

1 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 929 859

सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशक [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 860

(ii) अभियोजन पक्ष ने आपत्तिजनक साक्ष्य दिखाने वाले दस्तावेज़ एकत्र किए हैं जो अपीलार्थी की मां और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर अचल संपत्तियों की खरीद सहित कई नकद लेनदेन और अन्य अवैध लेनदेन का खुलासा करते हैं, जिसमें आरोपी-सूर्यकांत तिवारी और अन्य की संलिप्तता दिखाई देती है, कि कैसे श्री सूर्यकांत तिवारी अपीलार्थी सहित छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नौकरशाहों की मिलीभगत से कोयला वितरण आदेशों के खिलाफ धन उगाही करते थे, और कैसे कथित धन उगाही का उपयोग रिश्ते के भुगतान और अपीलार्थी सहित नौकरशाहों के लिए अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया जा रहा था।

(iii) अपीलार्थी, सी. एम. ओ. के ओ. एस. डी. के रूप में संलग्न उप सचिव, हालांकि अपेक्षाकृत एक कनिष्ठ अधिकारी थी, वह उच्च राजनीतिक शक्तियों तक अपनी पहुंच के कारण काफी प्रवाह और

नियंत्रण का प्रयोग करती थी, और आरोपी-सूर्यकांत तिवारी सिंडिकेट और जबरन वसूली रैकेट को केवल इसलिए संचालित करने में सक्षम था क्योंकि उसे अपीलार्थी का समर्थन प्राप्त था।

(iv) जाँच से पता चला है कि अपीलकर्ता सूर्यकांत तिवारी द्वारा संचालित जबरन वसूली रैकेट के निर्माण में प्रमुख व्यक्तियों में से एक था और श्री सूर्यकांत तिवारी द्वारा लगभग Rs.540 करोड़ की उगाही की गई थी। इसके अलावा, श्री मनीष उपाध्याय, जो सूर्यकांत तिवारी के रिश्तेदार थे, और जो अपीलार्थी के करीबी सहयोगी थे, का उपयोग सूर्यकांत तिवारी और अपीलार्थी के बीच नकद लेनदेन के लिए सुरक्षा की एक परत के रूप में किया गया था।

(v) अपीलार्थी ने कथित तौर पर जबरन वसूली गिरोह से प्राप्त धन का उपयोग उसकी माँ (शांति देवी चौरसिया), उसके चचेरे भाई (अनुराग चौरसिया) और उसके पति (सौरभ मोदी) के नाम पर संपत्तियों की खरीद के लिए किया था, जिसका विवरण अभियोजन की शिकायत में दिया गया है।

(vi) पी. एम. एल. ए. की धारा 45 के परन्तुक में "हो सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग इंगित करता है कि परन्तुक का लाभ अनिवार्य रूप से या स्वचालित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है, और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालयों द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना है।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

### विश्लेषण

18. पी. एम. एल. ए. के उद्देश्य को शायद ही चित्रित करने की आवश्यकता है। उक्त अधिनियम को धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्ति और उससे जुड़े और उससे आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। धारा 2 (1) (पी) के अनुसार, "धन शोधन" का अर्थ धारा 3 में दिया गया है। धन शोधन के अपराध को धारा 3 की अवहेलना की गई है, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है। धारा 45 पी. एम. एल. ए. के तहत अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाती है। जहां तक धारा 45 (1) में निहित जमानत देने की दोहरी शर्तों का संबंध है, विजय मदनलाल (उपरोक्त) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 45 के अंतर्निहित सिद्धांतों और कठोरताओं को लागू किया जाना चाहिए और अधिनियम के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए बिना किसी अपवाद के गणना की जानी चाहिए, जो कि धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए कड़े नियामक उपायों का प्रावधान करने वाला एक विशेष कानून है।

19. यद्यपि यह सत्य है कि न्यायालय को जमानत की मांग करने वाले आवेदन पर विचार करते समय जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य को सावधानीपूर्वक तौलना आवश्यक नहीं है, फिर भी न्यायालय को आरोप की प्रकृति, उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य की प्रकृति, कथित अपराध के लिए निर्धारित सजा की गंभीरता, अभियुक्त के चरित्र, ऐसी परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के लिए

विशिष्ट हैं, मुकदमे के समय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाह के नरम होने की उचित आशंका, जनता/राज्य के बड़े हित आदि को ध्यान में रखना चाहिए। यद्यपि जमानत देने या देने से इनकार करते समय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निर्णय अस्थायी प्रकृति के होंगे, फिर भी न्यायालय से जमानत देने या देने से इनकार करते समय प्रथम दृष्टया राय व्यक्त करने की अपेक्षा की जाती है जो विशेष रूप से गंभीर आर्थिक संकटों से निपटने के लिए विवेकपूर्ण अनुप्रयोग को प्रदर्शित करेगा।<sup>20</sup> जैसा कि ऊपर कहा गया है, पूरक शिकायत 30.01.2023 पर अन्य अभियुक्तों के साथ अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ जांच का सारांश उसके पैरा 8 में दर्ज किया गया है। प्रत्यर्थी-ईडी द्वारा की गई जांच का विवरण पैरा 9 में बताया गया है और धन शोधन के कथित अपराध में अपीलार्थी सहित प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका उसके पैरा-10 में बताई गई है, जो निम्नानुसार है:

- 861

सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशक [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 862

**“10.** धनशोधन अपराध में अभियुक्त की भूमिका।

ए. श्रीमती के खिलाफ धन शोधन के सबूत। सौम्या चौरसिया -

श्रीमती सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा की अधिकारी हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कार्यालय में उप सचिव के रूप में तैनात किया गया था और वे मुख्यमंत्री के ओएसडी के रूप में काम कर रही थीं। नौकरशाही पदानुक्रम में अपेक्षाकृत बहुत जूनियर होने के बावजूद, उन्होंने उच्च राजनीतिक शक्तियों तक अपनी सीधी पहुंच के कारण अभूतपूर्व शक्ति और नियंत्रण का आनंद लिया।

आयकर विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी और पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत की गई तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के विश्लेषण से पता चला है कि श्रीमती. मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत उप सचिव सौम्या चौरसिया, श्री सूर्यकांत तिवारी की अध्यक्षता में सिंडिकेट के निर्माण में प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। इस परिमाण और प्रकृति का जबरन वसूली रैकेट तभी संभव हुआ जब कई राज्य एजेंसियां स्थापित हुईं और सभी ने सूर्यकांत तिवारी के अवैध कृत्यों का समर्थन किया। यह सौम्या चौरसिया द्वारा संभव बनाया गया था ताकि कोयला खनन जिलों में कुशल अधिकारियों को तैनात किया जा सके जो सूर्यकांत तिवारी की बात सुनें। इसके अलावा, यह एक अलिखित नियम था कि सूर्यकांत तिवारी के निर्देशों का अर्थ सौम्या चौरसिया की आवाज और होने वाली शक्तियां थी। तथ्य यह है कि सूर्यकांत तिवारी का उनके साथ व्यक्तिगत और करीबी आधिकारिक लेन-देन था और वे कार्यालय के अधिकारियों को उनके निर्देश दे रहे थे, सूर्यकांत तिवारी के लिए वरिष्ठ जिला स्तर के अधिकारियों की कमान संभालना भी संभव हो गया। यह अवैध अधिकार उनके लिए कोयला और लोहे के छरों के परिवहन से अवैध जबरन वसूली के अपने साम्राज्य को चलाने के लिए आवश्यक था। उनकी सहमति के बिना, जिला तंत्र द्वारा कोई एन. ओ. जी. जारी नहीं किया गया था। यह सब इस तथ्य से संभव हुआ कि वे श्रीमती सौम्या चौरसिया की अच्छी पुस्तकों में थे। इसलिए, वह सीधे तौर पर पी. एम. एल. ए., 2002 की

धारा 3 की अवहेलना करते हुए धन शोधन की प्रक्रिया में शामिल हो गई है, जो वास्तव में धन शोधन की प्रक्रिया में कब्जे, छिपाने, उपयोग, अधिग्रहण और अपराध की आय को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने के माध्यम से शामिल है।

जाँच के निष्कर्षों के अनुसार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सौम्या चौरसिया ने सीधे तौर पर पी. एम. एल. ए., 2002 की धारा 2 (एल) (यू) के तहत अपराध की आय अर्जित की है। 30.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

करोड़।ईडी की जांच से यह स्पष्ट होता है कि हालांकि कोयला और लोहे के छरों के परिवहन पर जबरन वसूली का सारा पैसा सूर्यकांत तिवारी के सिंडिकेट द्वारा एकत्र किया गया था, लेकिन वह इस घोटाले का वित्तीय सहायक नहीं था। उन्होंने बेनामी संपत्ति खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में धन का उपयोग किया, लेकिन धन का बड़ा हिस्सा सौम्या चौरसिया को हस्तांतरित कर दिया गया, राजनीतिक धन पर खर्च किया गया और उच्च शक्तियों के निर्देशों के अनुसार स्थानांतरित किया गया।

श्री सूर्यकांत तिवारी के रिश्तेदार श्री मनीष उपाध्याय श्रीमती सौम्या चौरसिया और श्री सूर्यकांत तिवारी दोनों के करीबी सहयोगी हैं। ईडी की जाँच ने स्थापित किया है कि श्री मनीष उपाध्याय को श्री सूर्यकांत तिवारी और श्रीमती सौम्या चौरसिया के बीच नकदी लेनदेन के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के रूप में शामिल किया गया था। वह श्री सूर्यकांत तिवारी से श्रीमती सौम्या चौरसिया तक नकदी पहुँचाता था।

ईडी की जांच से पता चला है कि श्रीमती सौम्या चौरसिया और उनके परिवार ने उस अवधि के दौरान अचल संपत्ति हासिल करने की कोशिश की जो कोयला वसूली घोटाले के साथ हुई थी। इन परिसंपत्तियों की पहचान की गई थी और उन्हें अनंतिम संलग्नक आदेश (ओं) जारी करके संलग्न किया गया था जैसा कि बाद के पैरासों में विस्तृत है।” 21. अपीलार्थी और श्री सूर्यकांत तिवारी के बीच, अपीलार्थी और श्री मनीष उपाध्याय के बीच, और अपीलार्थी और श्री अनुराग चौरसिया के बीच मजबूत संबंधों से संबंधित साक्ष्य; श्री सूर्यकांत तिवारी द्वारा संचालित जबरन वसूली सिंडिकेट से अर्जित धन के स्थानांतरण के साक्ष्य, अपीलार्थी के प्रतिनिधि मनीष उपाध्याय को; अपराध की आय का उपयोग और अपीलार्थी द्वारा उसकी माँ शांति देवी और चचेरे भाई श्री अनुराग चौरसिया के नाम पर संपत्तियों का अधिग्रहण, उक्त संपत्तियों के विवरण के साथ आदि। उक्त अभियोजन शिकायत में विस्तार से बताया गया है, जो न्यायालय के दिमाग में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि प्रथम दृष्टया अपीलार्थी को धन शोधन के अपराध में शामिल पाया गया है जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है।

22. अदालत के समक्ष विचार के लिए अगला सवाल यह है कि क्या अपीलार्थी को एक महिला होने के नाते पीएमएलए की धारा 45 के पहले परंतुक का लाभ दिया जाना चाहिए, जो निम्नानुसार है:-

## “45. संज्ञेय और गैर-जमानती होना अनिवार्य है।-

(1) .....

863

सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशक [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 864

बशर्ते कि एक व्यक्ति जो सोलह वर्ष से कम आयु का है या एक महिला है या बीमार है या संक्रमित है [या अपने दम पर या एक करोड़ रुपये से कम की राशि के धन-शोधन के अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आरोपी है], उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष अदालत ऐसा निर्देश देती है: (2) .....

23. हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ। प्रीति चंद्र ने एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में दिनांकित **04.08.2023** आदेश में अवलोकन किया। **2023** की सं. **7409** निम्नानुसार है:-

“धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 का प्रावधान अदालत को जमानत देने का विवेकाधिकार प्रदान करता है जहां आरोपी एक महिला है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 के समान प्रावधानों की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा इस अर्थ में की गई है कि वैधानिक प्रावधान का मतलब यह नहीं है कि धारा 437 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। (प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम एन. सी. टी., दिल्ली और एक अन्य (2001) 4 एस. सी. सी. 280) देखें।”

24. धारा 45 के पहले परंतुक में “हो सकता है” अभिव्यक्ति का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी के लिए उक्त परंतुक का लाभ प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायालय के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है, और उन्हें रिहा करने के लिए न्यायालय की ओर से अनिवार्य या अनिवार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। सोलह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, महिलाओं, बीमार या असंवेदनशील व्यक्तियों की श्रेणी को जमानत देने के लिए इसी तरह का परोपकारी प्रावधान धारा 437 में किया गया है और कई अन्य विशेष अधिनियम भी बनाए गए हैं, हालांकि किसी भी तरह की कल्पना से इस तरह के प्रावधान को अनिवार्य या अनिवार्य प्रकृति के रूप में नहीं समझा जा सकता है, अन्यथा ऐसे विशेष अधिनियमों के तहत सभी गंभीर मामले महिलाओं और 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शामिल करते हुए किए जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालतों को धारा 45 के पहले प्रावधान में शामिल व्यक्तियों की श्रेणी और अन्य अधिनियमों में इसी तरह के प्रावधानों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होने की आवश्यकता है, क्योंकि कम उम्र के व्यक्तियों और महिलाओं, जिनके अधिक असुरक्षित होने की संभावना है, का कभी-कभी बेईमान तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है और ऐसे अपराधों को करने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा सकता है, फिर भी, अदालतों को इस तथ्य से भी अनजान नहीं होना चाहिए कि आजकल समाज में शिक्षित और अच्छी स्थिति में रहने वाली महिलाएं वाणिज्यिक उद्यमों और उद्यमों में खुद को संलग्न करती हैं, और विज्ञापन या अनजाने में

[2023] 15 एस सी आर।

अवैध गतिविधियों में खुद को संलग्न करें। संक्षेप में, अदालतों को धारा 45 पी. एम. एल. ए. के पहले परंतुक का लाभ उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी को देते हुए विवेकपूर्ण तरीके से अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। कथित अपराधों में ऐसी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की संलिप्तता की सीमा, जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की प्रकृति आदि भौतिक विचार होंगे।

25. तत्काल मामले में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र किए गए पर्याप्त साक्ष्य हैं जो प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलकर्ता जो मुख्यमंत्री के कार्यालय में उप सचिव और ओ. एस. डी. थे, पी. एम. एल. ए. की धारा 3 की अवहेलना करते हुए धन शोधन में सक्रिय रूप से शामिल थे। इसके विपरीत, न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी कथित अपराध का दोषी नहीं है और धारा 45 के परंतुक में विचार के अनुसार विशेष लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए जो एक महिला है।

26. अदालत ने अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ अग्रवाल के प्रस्तुत करने में यह भी कोई सार नहीं दिखाया कि अनुसूचित बंद यानी धारा 384 और 120 बी को आरोपी सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ बेंगलुरु के काडुगोडी पुलिस स्टेशन में दर्ज 2022 की प्राथमिकी संख्या 129 के संबंध में प्रस्तुत आरोप पत्र से हटा दिया गया है, और एसीजेएम बेंगलुरु ने आईपीसी की धारा 204 और 353 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लेते हुए, जो पीएमएलए अधिनियम के तहत निर्धारित नहीं हैं, विवादित आदेश पारित होने के समय कोई अनुसूचित बंद नहीं बचा था और यह कि कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना थी/हैं।

27. इस तथ्य के अलावा कि न तो आई. डी. 1 दिनांकित आरोप पत्र और न ही संज्ञान आदेश आई. डी. 2 उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों के दौरान रिकॉर्ड पर रखे गए थे क्योंकि वे उस समय कभी मौजूद नहीं थे, आई. ओ. ने आरोप पत्र में उक्त एफ. आई. आर. नं. सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ 2022 की धारा 129 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "जैसा कि आरोपी (सूर्यकांत तिवारी) को छत्तीसगढ़ राज्य में अपने गुर्गों के साथ आई. पी. सी. की धारा 384 के तहत अपराध के लिए प्रतिबद्ध पाया गया है, जिसके लिए उचित माध्यम से छत्तीसगढ़ पुलिस से रिपोर्ट मांगी जाएगी।" अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त एफ. आई. आर. के संबंध में आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय आई. ओ. द्वारा धारा 384 के तहत अपराध को हटा दिया गया था।

865

सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशक [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

28. इसके अलावा, यह ध्यान रखना बहुत ही उचित है कि जब एफ. आई. आर. विशेष अपराधों के तहत दर्ज की जाती है, जिसमें पी. एम. एल. ए. की अनुसूची में उल्लिखित अपराध शामिल हैं, तो यह सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत है, जो यह तय करेगी कि आरोपी के खिलाफ आरोप निर्धारित

करने की आवश्यकता है या नहीं।आई. ओ. द्वारा आरोप पत्र में उल्लिखित ऑफ एनस को कभी भी अंतिम निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है कि क्या पी. एम. एल. ए. में निर्धारित ऑफ एनस मौजूद थे या नहीं, विशेष रूप से जब अभियुक्त के खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर. में इनका उल्लेख किया गया था।जैसा कि विजय मदनलाल (उपरोक्त) मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया है, यह केवल उस स्थिति में है जब किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि में नामित व्यक्ति को आरोपमुक्त करने, बरी करने के आदेश के कारण या उसके खिलाफ आपराधिक मामले (अनुसूचित अपराध) को रद्द करने के कारण सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति के खिलाफ धन शोधन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जो कथित अनुसूचित अपराध से जुड़ी संपत्ति के संबंध में उसके माध्यम से दावा करता है।

29. तत्काल मामले में, सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा न तो आरोपमुक्त किया जाता है और न ही बरी किया जाता है और न ही आपराधिक मामले को रद्द किया जाता है।

30. मामले के उस दृष्टिकोण में न्यायालय तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं रखता है।चूंकि न्यायालय ने पाया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को लागू करने के लिए अपील में गलत बयान देकर तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास अपीलार्थी द्वारा और उसकी ओर से किया गया था, इसलिए अपील खारिज की जानी चाहिए और तदनुसार एक लाख रुपये की लागत के साथ खारिज की जानी चाहिए, जिसे अपीलार्थी द्वारा आज से दो सप्ताह के भीतर उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा प्राधिकरण के समक्ष जमा किया जाएगा।31. अपील तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान